Prabhat Khabar (Date: - 28/09/2019)

नयी तकनीक से होगी सड़कों की निगरानी व रखरखाव : मुख्यमंत्री

➲ ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में टास्क

संवाददाता ▷ पटना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पुल व सड़कों की रखरखाव व निगरानी नयी तकनीक से की जायेगी. उन्होंने पथ निर्माण व ग्रामीण कार्य विभाग को पुलों के रखरखाव के लिए जल्द ही मेंटेनेंस पालिसी तैयार करने को कहा. शुक्रवार को एक अणे मार्ग पर आयोजित ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सात निश्चय योजना के तहत बन रहे टोला संपर्क योजना का काम 2020 तक पूरा कर लेने का टास्क दिया. सीएम ने कहा कि आवागमन को सुगम बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है, उसका उद्देश्य लोगों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुंचाना है. गांव में पक्की गली का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे और उसकी लगातार निगरानी हो. सीएम ने कहा कि हम जब भी दौरे पर निकलते हैं, तो सड़कों की गुणवत्ता को देखते हैं. साथ ही एरियल सर्वे के दौरान भी इसका अवलोकन करते हैं. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि वह अपने स्तर से पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की बैठक कर पुल मेंटेनेंस पॉलिसी को अंतिम रूप दें.

सड़कों के किनारे पौधे लगाने का आदेश : मुख्यमंत्री ने बिहार के हरित आवरण को बढ़ाने के लक्ष्य को देखते हुए सड़कों के किनारे पौधे लगाने और जिन सड़कों के किनारे ज्यादा ऊंचाई है, वहां दो कतार में पौधे लगाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी करने वाले इंजीनियरों को नयी पॉलिसी और स्कीम के बारे में जानकारी और ट्रेनिंग देने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार, सीएम के सचिव मनीष कुमार वर्मा व अनुपम कुमार, सीएम सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह, सीएम के ओएसडी गोपाल सिंह सहित अधिकारी व इंजीनियर मौजूद थे.

मित्तनघाट से खाजेकलां घाट तक बनेगा एप्रोच रोड

पटना. पटना में मित्तनघाट से खाजेकलां घाट सहित पांच जिले की सड़कों को बनाने व मरम्मती के लिए पथ निर्माण विभाग ने 183.62 करोड़ की मंजूरी दी है. इसमें राजगीर बाइपास, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर व गया शामिल है. सभी पांच जिलों में 36.83 किमी की लंबाई में सड़कों की मरम्मती व निर्माण होगा. पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव कहा कि पटना के पूर्वी भाग में मित्तनघाट से खाजेकलां घाट तक एप्रोच रोड बनेगा. इसके लिए छह करोड़ की मंजूरी दी गयी है. राजगीर बाइपास रोड में लगभग साढ़े छह किमी लंबाई में सड़क बनाने के लिए 129 करोड़ की मंजूरी दी है.

Prabhat Khabar (Date: - 28/09/2019)

ब्रांडिंग के लिए किया जायेगा करार

फ्लिप कार्ट व रेमन इंडिया अब बेचेगी बिहार की खादी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते उद्योग मंत्री श्याम रजक व अन्य.

तीन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन

संवाददाता ▷ पटना

बिहार की खादी की ब्रांडिंग के लिए प्रदेश सरकार फ्लिप कार्ट और रेमन इंडिया जैसी प्रतिष्ठित मार्केटिंग कंपनियों से करार करने जा रही है. इससे पहले अमेजन इंडिया से इसी संदर्भ में करार किया जा चुका है. प्रदेश के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने यह जानकारी शुक्रवार को सूचना भवन स्थित सभागार में आयोजित एक औपचारिक संवाददाता सम्मेलन में साझा की. उद्योग मंत्री ने बताया कि पटना में तीन मंजिल खादी मॉल का निर्माण किया जा चुका है. इसका उद्घाटन तीन अक्तूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. उन्होंने बताया कि बिहार की खादी को डिजाइन करने और उसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए निफ्ट, एमबीए डिग्री धारी और दूसरे पेशेवर युवाओं को लगाया गया है. ताकि हम वर्ल्ड क्लास खादी का न केवल उत्पादन कर सकें,बल्कि प्रदेश के खादी वस्त्रों के डिजाइन भी बेहतर हों. बातचीत के दौरान उन्होंने साफ किया कि मॉल में प्रदेश के खादी उत्पादकों से खादी खरीदकर बेची जायेगी. यहां स्थायी तौर पर स्टॉल लगाये जायेंगे. प्रदेश के खादी उत्पादकों को अच्छा मुनाफा दिलाया जायेगा.

एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि उत्पादकों और विक्रेताओं के बीच किसी भी सूरत में बिचौलियों का प्रवेश नहीं होने दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि अक्टूबर, 2019 से मॉल कार्य करना प्रारंभ कर देगा.बिहार राज्य खादी बोर्ड अपने उत्पादों एवं दूसरे राज्यों के उत्पादों पर गांधी की मूर्ति चर्खा से सुशोभित बारकोड अंकित करेगा. उद्योग मंत्री ने बताया कि बेस लाइन सर्वे के आधार पर खादी नीति बनायी जा रही है.

Prabhat Khabar (Date: - 28/09/2019)

राज्य की सड़कों पर 2020 से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

संवाददाता ▷ पटना

परिवहन विभाग राज्य भर में इलेक्ट्रिक कार, बाइक और सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार है. विभाग ने नीति आयोग को प्रस्ताव भेजा है, जहां से मंजूरी के बाद अगले साल जनवरी से 30 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी. अधिकारियों के मुताबिक परिवहन विभाग की 25 से अधिक बसों को सीएनजी में बदलने पर काम चल रहा. इसके लिए कुछ माह पूर्व परिवहन अधिकारियों की एक टीम दिल्ली भी गयी थी, जहां कुछ बसों को सीएनजी में बदला गया है.

इलेक्ट्रिक कार पर होगा हरे रंग का नंबर प्लेट, रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट : इलेक्ट्रिक कार की खरीद अन्य विभागों में भी की जायेगी. सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर हरे रंग के नंबर प्लेट होंगे, जो पर्यावरण सुरक्षा के प्रतीक माने जायेंगे. साथ ही, इलेक्ट्रिक कार की खरीद करने पर रोड टैक्स में भी 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी.

कम खर्च में कर पायेंगे लोग अधिक दूरी तय

इलेक्ट्रिक कार की परिचालन लागत डीजल और पेट्रोल से बहुत कम है. मात्र 80 पैसे प्रति किलोमीटर के खर्च पर यात्रा कर सकेंगे. एक बार चार्ज कराने के बाद 142 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं. फुल चार्ज करने में 50 मिनट का समय लगेगा.

राज्य भर में लगेंगे चार्जिंग स्टेशन : इलेक्ट्रिक कारों के लिए पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के महत्वपूर्ण इलाकों में चार्जिंग स्टेशन लगाये जायेंगे, जहां लोग वाहन चार्ज कर सकेंगे. चार्ज करने का कुछ चार्ज लिया जायेगा.

इलेक्ट्रिक कार के फायदे : प्रदूषण कम होगा और ईंधन की बचत होगी. वहीं लोग कम कीमत में अधिक दूरी तक सफर तय कर पायेंगे. बसें इको फ्रेंडली होंगी.

Prabhat Khabar (Date: - 28/09/2019)

पटना मेट्रो ● **पटना में भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 3401 करोड़**

पीक आवर में 25 हजार करेंगे मेट्रो का सफर

संवाददाता ▷ पटना

पटना मेट्रो के डीपीआर में पीक ऑवर के दौरान लोगों के आवागमन का भी आकलन तैयार किया गया है. जानकारी के अनुसार तैयार होने के पहले वर्ष में दोनों फेजों को मिलाकर कुल 25 हजार से अधिक लोग मेट्रो की सवारी करेंगे. इसमें दानापुर मीठापुर वाया पटना जंक्शन वाले कैरिडोर में 14481 व दूसरे कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन टू न्यू आइएसबीटी वाया गांधी मैदान में 10689 लोग सफर करेंगे. उसी प्रकार वर्ष वर्ष 2031 में बढ़ कर पहले कैरिडोर 22488 लोग, वर्ष 2041 में 25255 और वर्ष 2051 में 31076 सफर करेंगे. इसके अलावा दूसरे कैरिडोर यानी पटना जंक्शन से न्यूआइएसबीटी जाने वाले मेट्रो में वर्ष 2024 में 10689 लोग से बढ़ कर वर्ष 2031 में 15613, वर्ष 2041 में 16733 लोग व वर्ष 2051 में 19467 लोगों के सफर का आकलन रखा गया है.

आमदनी का भी आकलन

पटना मेट्रो को लेकर बनाये गये डीपीआर में वर्षवार आमदनी का अभी आकलन किया गया है. इसमें वर्ष 2024-25 से लेकर वर्ष 2051-52 तक के रेवेन्यू का ब्योरा तैयार किया गया है. जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो के परिचालन के पहले वर्ष यानी 2024-25 में निर्माण लागत के लगभग दस फीसदी आमदनी का आकलन किया गया है. इसके बाद वर्ष 2031-32, वर्ष 2041-42 और वर्ष 2051-52 तक आमदनी का खाका भी डीपीआर में तैयार कर लिया गया है. डीपीआर के अनुसार किराया व नॉन फेयर में अलग अलग आमदनी रखी गयी है. इसके अलावा मेट्रो के एलाइमेंट व डीपो निर्माण में भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपये खर्च होने का प्रावधान रखा गया है.

ऐसे होगी आमदनी

डीपीआर में दिये गये ब्योरा के अनुसार वर्ष 2024-25 में किराया के माध्यम से 913 करोड़, वर्ष 2031-32 में 1848 करोड़, वर्ष 2041-42 में 2949 करोड़ व वर्ष 2051-12 में 4706 करोड़ रुपये तक रखा गया है. जबकि, नान फेयर को मिला कर वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़, वर्ष 2031-32 में 2305 करोड़, 2041-42 में 3205 करोड़ व वर्ष 2051-12 में 5942 करोड़ रुपये आमदनी का आकलन रखा गया है.

डिपो के लिए जगह

इतवारपुर व आइएसबीटी में दो जगहों पर बनने वाले पटना मेट्रो के डीपो के लिए जमीन की जरूरत भी तैयार कर ली गयी है. इसमें इतावारपुर में बनने वाले डीपो के लिए 14.4 हेक्टेयर और न्यू आइएसबीटी के पास बनने वाले डीपो के लिए 12.5 हेक्टेयर यानी कुल मिला कर 26.9 हेक्टेयर भूमि की जरूरत पड़ेगी.

Prabhat Khabar (Date: - 28/09/2019)

आद्री के परिसर का सीएम ने किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट आद्री के पुनर्निर्मित परिसर का शुक्रवार को उद्घाटन किया . अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया . आद्री द्वारा सीएम को मोमेंटो भेंट किया गया . उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस की अध्यक्षता की . मौके पर उद्योग मंत्री श्याम रजक, जल संसाधन मंत्री संजय झा, आद्री के सदस्य सचिव शैवाल गुप्ता, सीएम के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव अनुपम कुमार, राज्य चुनाव आयुक्त एके चौहान, जगजीवन राम शोध संस्थान के निदेशक श्रीकांत, सत्यजीत सिंह, आद्री के निदेशक प्रो प्रभात पी घोष मौजूद थे.

Prabhat Khabar (Date: - 28/09/2019)

राज्यपाल से भारतीय विदेश सेवा के अफसरों ने की मुलाकात

संवाददाता ▷ पटना

बिहार दौरे पर आये भारतीय विदेशी सेवा के अफसरों से मिलते राज्यपाल फागू चौहान.

राज्यपाल फागू चौहान से शुक्रवार को बिहार दौरे पर आये भारतीय विदेश सेवा के तीन अधिकारियों, केन्या में तैनात उप उच्चायुक्त आशीष कुमार सिन्हा,मनु स्मृति एवं स्वधा रिजवी ने राजभवन में मुलाकात की.राज्यपाल चौहान ने भारतीय विदेश सेवा के तीनों अधिकारियों को बिहार आने पर शुभकामनाएं दीं.

राज्यपाल चौहान ने इन अधिकारियों को बताया कि बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत समृद्ध रही है. यहां बोधगया, नालंदा, राजगीर, विक्रमशिला, वैशाली जैसे कई अहम पर्यटन स्थल हैं. बताया कि बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिए आकर्षण के प्रमुख केन्द्र बोधगया की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है.उन्होंने कहा कि पूर्वजों को श्रद्धा स्वरूप पिंडदान और तर्पण करने 'पितृपक्ष' में लाखों श्रद्धालु गया आते हैं. उन्होंने अधिकारियों को राजगीर, नालंदा, विक्रमशिला आदि की शैक्षिक दृष्टि से विशेष महत्ता की भी जानकारी दी.

राज्यपाल ने कहा कि बिहार–बंटवारे के बाद झारखंड राज्य में अधिकांश खनिज–संपदा चले जाने के बाद बिहार का आर्थिक विकास अब कृषि पर निर्भर है. उन्होंने कहा कि खाद्य–प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास हो रहे हैं.राज्यपाल ने 'कृषि रोड मैप' के बारे में जानकारी साझा की.

राज्यपाल ने बताया कि बिहार आपदा प्रभावित राज्य है. इसका आधा हिस्सा अक्सर सुखाड़ तो आधा बाढ़ से तबाह हो जाता है.

राज्यपाल ने अधिकारियों को बताया कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता–विकास के प्रयासों को तेज करने के लिए सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों के सत्रों को नियमित करने के लिए कहा है.

इस दौरान अधिकारियों ने विदेश सेवा में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि केन्या जैसे कई देश भारत की प्रगति के साथ उसके विभिन्न राज्यों के विकास में भी रुचि रखते हैं. अधिकारियों ने कहा कि बिहार राज्य के पर्यटन स्थलों की महत्ता से विदेश में अवगत कराया जायेगा. मुलाकात के दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी उपस्थित रहे.

Prabhat Khabar (Date: - 28/09/2019)

आस्था ● प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारों को पत्र भेज मांगी यात्रा में जाने वालों की सूची

प्रकाश पर्व में शामिल होने ननकाना साहिब जायेगी संगत

प्रतिनिधि ▷ पटना सिटी

सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज की जन्मस्थली ननकाना साहिब (पाकिस्तान) जाने के लिए इच्छुक सिख संगतों से प्रबंधक कमेटी ने सूची मांगी है. इसके लिए तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधक कमेटी के महासचिव महेंद्रपाल सिंह ढिल्लन ने तख्त साहिब से जुड़े गुरुद्वारों के साथ अन्य गुरुद्वारों को यह पत्र भेजा गया है. महासचिव ने संगत को कहा है कि नवंबर माह में आयोजित होने वाले 550 वें प्रकाश पर्व को लेकर ननकाना साहिब व श्री सच्चा सौदा की यात्रा के लिए इच्छुक संगत की सूची पासपोर्ट, पहचानपत्र व स्थायी पते के प्रमाणपत्र के साथ जल्द- से- जल्द उपलब्ध करायी जाये. उपलब्ध सूची गृह विभाग को भेजी जायेगी. दरअसल मामला यह है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने बिहार सरकार के गृह विभाग को पत्र भेज कर प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए सिख संगतों की सूची मांगी थी. इसी के आलोक में महासचिव ने बिहार व केंद्र सरकार के मिले पत्र के आधार पर प्रकाश पर्व में शामिल होने वाली संगत के लिए सूची उपलब्ध कराने को कहा है. महासचिव ने बताया कि पाकिस्तान जाने वाली सिख संगतों की सूची मिलने के उपरांत गृह विभाग को भेजी जायेगी, जहां से निर्णय के आलोक में संगत पाकिस्तान में आयोजित प्रकाश पर्व में शामिल हो सकती है.

प्रबंधक कमेटी की बैठक स्थगित होने पर सेवादारों में आक्रोश

- करेंगे आंदोलन की रूपरेखा तय
- कल बुलायी है बैठक

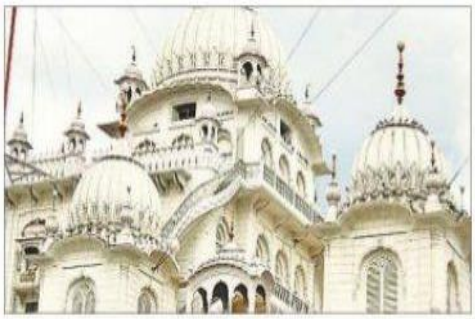

पटना सिटी. तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधक कमेटी की 30 सितंबर को प्रस्तावित बैठक स्थगित होने का मामला प्रकाश में आने के बाद सेवादारों में आक्रोश है. ऐसे में सेवादार समाज कल्याण समिति की ओर से रविवार 29 सितंबर को तख्त साहिब के दर्शन ड्योढ़ी में सेवादारों की बैठक बुलायी गयी है. समिति के अध्यक्ष सरदार त्रिलोक सिंह निषाद ने बताया कि बैठक में सेवादारों की लंबित 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की जायेगी ताकि प्रबंधक कमेटी सेवादारों की लंबित मांगों की मूर्ति कर सके. अध्यक्ष की मानें तो बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की जायेगी. दरअसल मामला यह है कि स्थगित हुई प्रबंधक कमेटी की बैठक के सेवादारों के सर्विस रूल से जुड़े मामले व लंबित मांगों को लेकर कमेटी में चर्चा होनी थी. ऐसे में बैठक नहीं होने से चर्चा नहीं हो पायेगी. नतीजतन बीते सात सितंबर से ही अपनी मांगों को लेकर संघर्ष की राह अपनाये सेवादार अब आर-पार की लड़ाई की मूड में हैं. अध्यक्ष ने बताया कि उनकी 19 सूत्री मांगों में सेवादारों की प्रमुख मांगों में कार्यरत 60 व 65 वर्ष की उम्र वाले सेवादारों को प्रबंधक कमेटी के सदस्य रिटायरमेंट करने की दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन पहले सेवादारों के लिए सर्विस रूल बना कर रिटायर करें. निलंबित सेवादारों की सेवा बहाल करने, सालाना वेतन वृद्धि का लाभ अप्रैल माह से देने, महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ाने, मृतक के आश्रितों को बकाया रकम जोड़ कर एक माह के अंदर भुगतान करने, एक सदस्य को नौकरी व विधवा को पेंशन देने, निलंबित सेवादारों को किराये की राशि व वेतन का आधा रकम देने समेत अन्य मांगें हैं.